भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1779
10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

ईवी चार्जिंग स्टेशन

1779. **श्री राजा राम सिंहः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के बावजूद देश भर में, विशेष रूप से टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे के कारण भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परिवर्तन बाधित हो रहा है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस कमी के क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) देश में आज की तिथि तक स्थापित और चालू सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है और 2030 तक लगभग 30 प्रतिशत ईवी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की अनुमानित कमी का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने चार्जिंग बुनियादी ढांचे में क्षेत्रीय असंतुलन का आकलन किया है, जो कुछ राज्यों और शहरी केंद्रों में केंद्रित है, और कम सेवा वाले क्षेत्रों में तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम प्रस्तावित हैं; और
(ङ) निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित ईची चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए 'फ़ेम' और पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनाओं के तहत वित्तीय प्रोत्साहन, लक्ष्य, समय-सीमा और निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) स्थापित करना एक लाइसेंसरहित गतिविधि के रूप में अधिसूचित किया गया है, और निजी संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के 17.09.2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्थापित करने की अनुमति है। इसके अलावा, सरकार ने देश भर में पब्लिक चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को समर्थन करने के उद्देश्य से टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे भारत में पर्याप्त सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना लगाने के लिए फ़ेम-II और पीएम ई-ड्राइव स्कीमों के तहत क्रमशः 912.50 करोड़ रुपए और 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है।

(ग): भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) से प्राप्त सूचनानुसार, देश में कुल 29,151 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन संस्थापित किए गए हैं।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 2030 तक चार्जिंग अवसंरचना में कमी का अनुमान लगाने के लिए कोई आकलन संबंधी अध्ययन नहीं किया है।

(घ): भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ईवी चार्जिंग अवसंरचना के वितरण में क्षेत्रीय असंतुलन के संबंध में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है, हालांकि, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए फ़ेम-II और पीएम ई-ड्राइव दोनों स्कीमें पूरे भारत में लागू की गई हैं।

(ङ): फ़ेम-II स्कीम के तहत, सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने के लिए 912.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, जिसमें से 633.44 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत, भारी उद्योग मंत्रालय ने 26.09.2025 को "ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना" के लिए संचालन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो पात्र सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की भागीदारी सहित चार्जिंग अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

****